

सेवा क्षेत्र

भारत के गतिशील सेवा क्षेत्र में विगत दशक में तेजी से विकास हुआ है और 2014-15 में भारत की स.घ.उ. का लगभग 72.4 प्रतिशत सेवा क्षेत्र से आया है। अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, भारत की विकास गाथा की अगुवाई सेवा क्षेत्र द्वारा की गई है जिसकी विकास-दर अब दो अंकों में है।

अंतरराष्ट्रीय तुलना

विश्व सेवाएं स.घ.उ.

7.2 2013 में 75.6 ट्रिलियन अमेरिकी डालर विश्व स.घ.उ. (वर्तमान मूल्यों पर) सेवाओं की हिस्सेदारी थोड़ी अधिक बढ़कर 66.0 प्रतिशत हो गयी, जबकि वृद्धि दर (स्थिर मूल्यों पर) कुछ कम होकर 2012 के बाद 2.1 प्रतिशत हो गयी। तथापि, विगत 12 वर्षों के दौरान विश्व स.घ.उ. में सेवा के हिस्से में 2.8 प्रतिशत बिंदु (पीपी) की गिरावट आई है। यूएस का सेवा स.घ.उ. के साथ ही समग्र स.घ.उ. में भी प्रथम स्थान है और चीन व जापान काफी दूर तथा द्वितीय व तृतीय स्थान पर हैं। 2013 में स.घ.उ. की दृष्टि से विश्व के शीर्ष 15 देशों में भारत का 10वां स्थान और सेवा स.घ.उ. की दृष्टि से 11वां स्थान है। तथापि, 2001-2013 की अवधि में इन शीर्ष 15 देशों में स.घ.उ. की सेवा हिस्सेदारी में अधिकतम बढ़ोतरी स्पेन (8.6 पीपी) द्वारा दर्ज की गई, इसके बाद भारत (5.7 पीपी) और चीन (3.6 पीपी) की बारी आती है। इस अवधि के दौरान सीएजीआर के 8.7 प्रतिशत रहने पर भारत तेजी से बढ़ रहे सेवा क्षेत्र में दूसरे स्थान पर था, जो चीन 10.7 प्रतिशत के ठीक नीचे है। इन शीर्ष 15 देशों में कुल स.घ.उ. में, सेवा क्षेत्र में केवल चीन का हिस्सा 50 प्रतिशत से कम है। (सारणी 7.1)।

विश्व सेवा रोजगार

7.3 2014 संबंधी रिपोर्ट के अनुसार, सेवा क्षेत्र का 2012 की तुलना में 2013 में 1.4 प्रतिशत की कुल

वैश्विक वृद्धि का आधे से भी अधिक योगदान है। विश्व भर में सेवा की हिस्सेदारी 2001 में 68.8 प्रतिशत से घटकर 2013 में 66 प्रतिशत रह गई है जबकि रोजगार में इसकी हिस्सेदारी 39.1 प्रतिशत से बढ़कर 45.1 प्रतिशत हो गई है। भारत और चीन को छोड़कर 15 शीर्ष देशों के लिए सेवा स.घ.उ. और सेवा रोजगार, दोनों का हिस्सा काफी अधिक और एक-दूसरे के काफी पास है। भारत में सेवा क्षेत्र की आय में हिस्सेदारी अधिक और रोजगार में अपेक्षाकृत कम है। लेकिन इन दोनों देशों में, विगत 12 वर्षों में स.घ.उ. और रोजगार, दोनों में सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई है।

विश्व सेवा व्यापार

7.4 2001-13 के दौरान विश्व व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात का सीएजीआर 10 प्रतिशत था और भारत का 20.1 प्रतिशत पर 15 शीर्ष सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष स्थान था, जिसके बाद 16.5 प्रतिशत पर चीन का स्थान था। 2013 में, 4.6 ट्रिलियन अमेरिकी डालर विश्व व्यावसायिक सेवाओं के निर्यातों में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। व्यावसायिक सेवाओं के सबसे बड़े निर्यातक, संयुक्त राष्ट्र के सेवा निर्यातों में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि भारत और चीन, दोनों देशों में परिवहन सेवाओं के निर्यात में 3 प्रतिशत तक की गिरावट के कारण चीन में 7.5 प्रतिशत और भारत में 3.6 प्रतिशत की कमी हुई। भारत और चीन के सेवा आयातों में क्रमशः 2.7 और 17.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सारणी 7.1: सेवाओं में प्रदर्शन: अंतरराष्ट्रीय तुलना

देश	सं.घ.उ. में		सेवा वृद्धि दर			सेवाओं का हिस्सा				सेवा निर्यात वृद्धि				
	समग्र	सेवा	प्रतिशत		सीएजीआर	स.घ.उ.		रोजगार		कुल		(प्रतिशत)सीएजीआर		
			वर्षानुवर्ष	2001-13	में	में	निर्यात में	वर्षानुवर्ष	2001-13					
यूएस	1	1	2.1	1.7	1.8	77.6	78.6	75.0	81.2	27.2	29.5	-3.6	5.0	7.7
चीन	2	2	10.3	8.3	10.7	40.5	46.1	27.7	35.7	11.0	8.5	9.1	7.5	16.5
जापान	3	3	1.3	0.8	0.7	69.0	72.4	63.9	69.7	13.6	16.9	-6.9	2.0	7.1
जर्मनी	4	4	3.1	0.1	0.9	68.8	68.4	64.6	70.2	12.8	16.5	5.6	7.8	10.7
फ्रांस	5	5	2.0	0.6	1.4	74.7	78.5	69.9	74.9	19.8	29.0	-0.5	9.7	9.5
यूके	6	6	3.4	2.0	2.2	73.6	79.2	73.8	78.9	30.1	35.1	-0.8	1.5	7.9
ब्राजील	7	8	1.8	2.1	3.5	67.1	69.4	59.4	62.7	13.0	13.4	-2.7	-1.7	12.9
इटली	8	7	2.3	-1.3	0.2	70.5	74.4	63.1	68.5	18.9	17.6	2.1	6.1	5.6
रूस	9	10	3.3	2.0	5.1	55.6	59.8	58.6	62.3	9.9	11.0	17.3	11.2	4.0
भारत	10	11	7.5	6.7	8.7	51.3	57.0	24.0	28.1	27.9	32.5	4.8	3.6	20.1
कनाडा	11	9	3.5	1.8	2.5	65.9	70.4	74.7	76.5	12.7	14.6	-3.6	0.0	6.2
आस्ट्रेलिया	12	12	3.7	2.5	3.0	69.9	69.7	74.2	75.5	21.8	17.1	-8.9	-0.1	9.4
स्पेन	13	13	4.0	-1.1	2.3	65.3	73.9	62.0	74.9	32.2	31.5	6.0	6.1	8.4
दक्षिण कोरिया	14	15	5.0	2.9	3.7	59.0	59.1	62.6	76.4	16.3	16.6	-4.9	1.3	15.7
मैक्सिको	15	14	1.1	2.4	3.2	57.7	58.9	56.1	61.9	7.2	4.9	-7.5	21.3	11.8
विश्व			2.5	2.1	2.5	68.8	66.0	39.1	45.1	19.4	19.8	0.1	5.6	9.9

स्रोत : स.घ.उ. के लिए संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा से परिगणित आंकड़े, रोजगार के लिए विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के डाटाबेस और सेवा व्यापार के लिए विश्व व्यापार संगठन डाटाबेस से परिगणित।

टिप्पणियाँ : रैंक और हिस्सेदारी, चालू मूल्यों (2013) पर आधारित है; वृद्धि दरें अचल मूल्यों (अमेरिकी डालर) पर आधारित हैं; निर्माण क्षेत्र में सेवा स.घ.उ. शामिल नहीं है; 2013 में रोजगार डाटा के लिए निकटतम पूर्व वर्षों के उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग किया गया है। *2012 आंकड़े।

7.5 2014 की पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में विश्व सेवा निर्यातों में क्रमशः 5.7 प्रतिशत, 6.4 प्रतिशत और 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत के सेवा निर्यात वृद्धि में पहली तिमाही में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन दूसरी और तीसरी तिमाही में 2.8 प्रतिशत और 2.7 प्रतिशत की कमी हुई है। इसकी सेवा आयात में वृद्धि पहली तिमाही में ऋणात्मक 3.9 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 0.3 प्रतिशत और तीसरी तिमाही में 2.7 की वृद्धि प्रतिशत थी।

विश्व सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

7.6 2014 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में कमजोर नीतिगत अनिश्चितता और विश्व-कूटनीतिक जोखिमों के कारण वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह में अनुमानित 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डालर, 8 प्रतिशत की गिरावट आई। चीन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में विश्व का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन गया जिसमें सेवा क्षेत्र में एफडीआई द्वारा प्रेरित 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि विनिर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट आई। भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी

निवेश में शीर्ष सेवा क्षेत्र में अंतर्वाह के कारण भी लगभग 26 प्रतिशत की गिरावट आई जो अनुमानित 35 बिलियन अमेरिकी डालर है जैसी भारतीय आंकड़ों से पुष्टि होती है।

भारत का सेवा क्षेत्र

7.7 देश और राज्यों की आय, व्यापार अंतर्वाह विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह और रोजगार में योगदान के संदर्भ में भारत का सेवा क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभर रहा है।

सेवा स.घ.उ. और सकल पूंजी निर्माण

7.8 भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की नई विधि के अनुसार, 2013-14 आधार मूल्यों (चालू मूल्यों) पर भारत के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का 51.3 प्रतिशत बैठता है जो कुल जीवीए वृद्धि की 6.6 प्रतिशत और बाजार मूल्यों पर 6.9 स.घ.उ. की तुलना में 9.1 प्रतिशत तक बढ़ा। एक बार्डर लाइन सेवा निर्माण सहित सेवा की हिस्सेदारी 59.6 प्रतिशत और वृद्धि 8.1 प्रतिशत है (सारणी 6.2)।

7.9 दिलचस्प है कि 2013 में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) में 35.4 लाख रु० के सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी

सारणी : 7.2 भारत के सेवा क्षेत्र का हिस्सा और वृद्धि (आधार मूल्य पर जीवीए)

(प्रतिशत)

	जीवीए			जीसीएफ	
	2012-13	2013-14	2014-15 [#]	2012-13	2013-14
कुल सेवाएं	50.0 (8.0)	51.3 (9.1)	53.0(10.6)	53.8 (-1.9)	54.6 (3.1)
व्यापार, मरम्मत, होटल व रेस्तरां	11.3 (10.3)	12.0(13.3)	18.7 (8.4) *	9.6 (46.9)	11.5 (21.2)
व्यापार व मरम्मत सेवाएं	10.2 (11.1)	11.0(14.3)		8.6 (59.9)	10.6 (23.5)
होटल और रेस्तरां	1.1 (3.3)	1.1 (3.9)		0.9 (-15.6)	0.9 (-0.3)
परिवहन, भंडारण और प्रसारण संबंधी सेवाएं (जिनमें से)	6.6 (8.4)	6.6 (7.3)		6.8 (-4.1)	5.5(-16.4)
रेलवे	0.8 (18.0)	0.8 (9.3)		1.1 (11.0)	1.2 (5.6)
सड़क परिवहन	3.3 (7.5)	3.2 (5.0)		2.5 (-16.6)	1.6(-35.8)
हवाई अड्डा	0.1 (-5.9)	0.1 (6.0)		0.2 (-11.4)	0.0(-72.4)
वित्तीय सेवाएं	5.9 (6.7)	5.8 (6.4)	20.9(13.7)^	1.3 (-9.8)	1.1(-10.6)
रियल एस्टेट, रिहाइश और व्यावसायिक सेवाएं	13.6 (9.8)	14.0 (8.5)		22.7 (-15.1)	20.1(-10.2)
सरकारी प्रशासन और रक्षा	6.0 (3.2)	6.0 (4.9)	13.4 (9.0)@	8.5 (1.7)	10.6 (26.3)
अन्य सेवाएं	6.6 (6.2)	6.9(10.7)		4.9 (4.2)	5.8 (20.3)
निर्माण	8.7 (-4.3)	8.3 (2.5)	8.0 (4.5)	5.8 (-11.5)	5.4 (-4.4)
कुल सेवाएं (+निर्माण)	58.7 (6.0)	59.6 (8.1)	61.0 (7.1)	59.6 (-3.0)	60.0 (2.4)
कुल जीवीए/जीएफसी	100.0 (4.9)	100.0 (6.6)	100.0 (7.5)	100.0 (-0.7)	100.0 (1.4)
स.घ.उ. (2011-12 के स्थिर बाजार मूल्य)	(5.1)	(6.9)	(7.4)		

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (कें सां सं)

नोट : हिस्सेदारी चालू मूल्यों और वृद्धि 2011-12 स्थिर मूल्य में है; कोष्ठक में आंकड़े वृद्धि दर दर्शाते हैं; # 2014-15 हेतु अग्रिम अनुमान। *में परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएं शामिल हैं, ^ में रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं शामिल हैं, @ में अन्य सेवाएं भी शामिल हैं। यह केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अपनाई गई नई विधि पर आधारित है।

सर्वाधिक (54.6 प्रतिशत) रही है। ऐसा “वास्तविक एस्टेट”, रिहाइश और पेशेवर सेवाओं के 20.1 प्रतिशत में सकल पूंजी निर्माण के कारण है हालांकि इसके हिस्से में विगत दो वर्षों में गिरावट आई है, जिसके बाद व्यापार और मरम्मत क्षेत्र (10.6 प्रतिशत) और “सरकारी प्रशासनिक और रक्षा” (10.6 प्रतिशत) की बारी आती है जहां हिस्सेदारी में सुधार आया है। सेवा सकल पूंजी निर्माण की 3.1 की प्रतिशत वृद्धि दर कुल सकल पूंजी निर्माण की अपेक्षा 1.4 प्रतिशत अधिक है। वास्तव में सेवा में धनात्मक सकल पूंजी निर्माण से कुल सकल पूंजी निर्माण में धनात्मक वृद्धि हुई क्योंकि कृषि और उद्योग में सकल पूंजी निर्माण क्रमशः -0.3 प्रतिशत और -0.6 प्रतिशत ऋणात्मक

रहा है। विनिर्माण में जीसीएफ वृद्धि और अधिक नकारात्मक -5.4 प्रतिशत थी।

7.10 कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने की पुरानी विधि के अनुसार सेवा क्षेत्र, स.घ.उ. का 57 प्रतिशत था, जो 2013-14 में वित्त, बीमा, रियल एस्टेट और व्यवसायिक सेवाओं में 12.9 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि के बावजूद व्यापार, होटल और रेस्तरां और परिवहन, भंडारण एवं संचार की मिश्रित श्रेणी की वृद्धि दर में गिरावट के कारण है जो 2012-13 में 5.1 प्रतिशत से 3.0 प्रतिशत रह गई। इन दो विधियों के तहत सेवा वृद्धि में कुछ भिन्न परिणाम आधार मूल्य पर कारक लागत से स.घ.उ. में अवधारणात्मक परिवर्तन और नवीनतम आंकड़ों

के स्रोतों को अपनाने के कारण है। नई विधि में सेवा के हिस्से में अत्यधिक गिरावट भी थी। व्यापार, मरम्मत, होटलों और रेस्तरां के हिस्से में प्रमुख परिवर्तन हुए क्योंकि पुरानी लागत कारक विधि में यह हिस्सा 2012-13 में 17.2 प्रतिशत था, जबकि आधार मूल्य पद्धति में यह गिरकर 11.3 प्रतिशत हो गया। ऐसा इस कारण है क्योंकि विनिर्माण कंपनियों द्वारा किया गया व्यापार से विनिर्माण में अंतरित हो गया है और असंगठित व्यापार उद्यमों के आंकड़े 1999-2000 सर्वेक्षण की बजाय 2010-11 के साथ अद्यतन किया गया है लेकिन इस क्षेत्र की वृद्धि, पुरानी विधि के विपरीत नई विधि में कहीं अधिक हुई थी।

7.11 अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सेवाओं क्षेत्र की वृद्धि 2013-14 में 9.1 प्रतिशत की अपेक्षा 2014-15 में और अधिक 10.6 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। ऐसा मुख्यतः पूर्व वर्ष में वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं में 13.7 प्रतिशत से 7.9 प्रतिशत और लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं में 13.7 प्रतिशत से 7.9 प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण है। यह 2014-15 में व्यापार, होटलों, परिवहन, संचार और संबंधित सेवाओं में 8.4 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि थी यद्यपि 2013-14 में यह 11.1 प्रतिशत पर निम्नतर था।

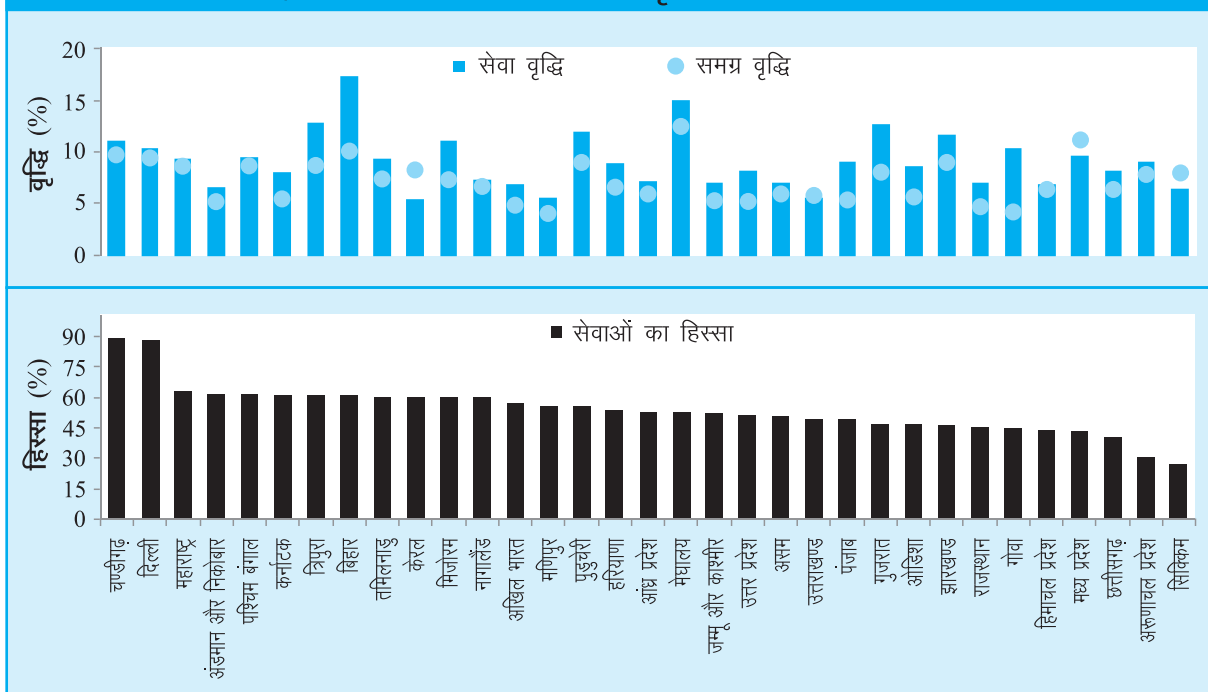
सेवाओं की राज्य-वार तुलना

7.12 यह सेवा क्षेत्र भारत के अधिकांश राज्यों में प्रमुख है। 2013-14 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में सेवाओं की हिस्सेदारी, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर 40 प्रतिशत से अधिक है। (चित्र 7.1)। चंडीगढ़ का स्थान 88.4 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ सबसे शीर्ष पर है जिसके बाद 87.7 प्रतिशत पर दिल्ली का स्थान है। अधिकांश राज्यों में प्रमुख सेवाओं में, व्यापार, होटल और रेस्तरां की हिस्सेदारी है और इसके बाद रियल एस्टेट, रिहायश के स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाओं की बारी आती है। दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ जैसे कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भी बैंकिंग और बीमा की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। 2013-14 में बिहार का 17.3 प्रतिशत की उच्चतम सेवा वृद्धि थी और उत्तराखंड की सबसे कम 5.5 प्रतिशत है। व्यापार, होटलों और रेस्तरां में उच्च वृद्धि के कारण विगत पांच वर्षों में सेवा क्षेत्र में बिहार में लगातार दो अंकीय वृद्धि दिखाई गई है।

भारत के सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

7.13 सेवा क्षेत्र के तहत विभिन्न गतिविधियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के वर्गीकरण में असदिग्धता बरकरार है। भारतीय प्रत्यक्ष निवेश की वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाओं,

चित्र 7.1: 2013-14, में सेवा क्षेत्र का हिस्सा और वृद्धि



स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़ों से परिगणित

टिप्पणी : हिस्सेदारी चालू मूल्यों पर वृद्धि दर स्थिर मूल्यों (2004-05) पर;

* 2012-13 के आंकड़े दर्शाता है।

सारणी 7.3: सेवा क्षेत्र में एफ डी आई इक्विटी अंतर्वाह							
रैंक	क्षेत्र	मूल्य (यूएस मिलियन में)			कुल प्रतिशत	वृद्धि दर	
		2013-14	2014-15 (अप्रैल-नवम्बर)	सेवाओं (अप्रैल 2000-नवम्बर 2014)		2013-14	2014-15 (अप्रैल-नवम्बर)
1	सेवा क्षेत्र (वित्तीय व गैर वित्तीय)	2225	1847	41307	17.5	-54.0	24.9
2	निर्माण विकास #	1226	703	24009	10.2	-8.0	-20.9
3	दूरसंचार *	1307	2472	16635	7.0	329.9	7390.9
4	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्ड वेयर	1126	862	13679	5.8	131.7	62.9
5	होटल व पर्यटन	486	544	7662	3.2	-85.1	180.4
	कुल 5 शीर्ष सेवाएं	6370	6428	103291	43.7	-37.6	105.8
	कुल एफडीआई अंतर्वाह	24299	18884	236465	100	8.4	22.2

स्रोत : औद्योगिक नीति और प्रोन्नति विभाग के आंकड़ों पर आधारित

टिप्पणी : # टाउनशिप, हाऊसिंग, निर्मित अवसंरचना को दर्शाता है; * रेडियो पेजिंग, सेलुलर मोबाइल, आधारभूत टेलीफोन सेवाओं को दर्शाता है।

निर्माण विकास, दूरसंचार कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और होटलों एवं पर्यटन की साझा हिस्सेदारी को सेवा एफडीआई-के सर्वश्रेष्ठ अनुमान के तौर पर देखा जा रहा है, यद्यपि इसमें कुछ सेवा भिन्न तत्व भी शामिल हो सकते हैं। यह हिस्सेदारी अप्रैल 2000-नवंबर, 2014 की अवधि के दौरान संचयी एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह की 43.7 प्रतिशत है। यदि व्यापार, सूचना और प्रसारण, निर्माण (अवसंरचना) गतिविधियों, परामर्श सेवाओं, अस्पताल और निदान केंद्रों, बंदरगाहों, कृषि सेवाओं, शिक्षा, हवाई भाड़े सहित वायु परिवहन और खुदरा व्यापार जैसी कुछ अन्य सेवाओं अथवा सेवा-संबंधी क्षेत्रों की हिस्सेदारी को शामिल किया जाए, तथा सेवा क्षेत्र को संचयी एफडीआई अंतर्वाह की कुछ हिस्सेदारी बढ़कर 53.8 प्रतिशत हो जाएगी। 2013-14 में, सेवा क्षेत्र (निर्माण सहित शीर्ष पांच क्षेत्र) में एफडीआई अंतर्वाह 8.4 प्रतिशत एफडीआई अंतर्वाह में समग्र वृद्धि में 6.4 बिलियन अमेरिकी डालर की 22.2 प्रतिशत की तीव्र गिरावट हुई। तथापि, 2014-15 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान, समग्र एफडीआई अंतर्वाह 32.6 प्रतिशत वृद्धि की अपेक्षा बढ़कर 105.8 प्रतिशत हो गया। इस वर्ष के प्रथम आठ माह में शीर्ष 5 सेवाओं के कुल एफडीआई अंतर्वाह, दूरसंचार में प्रमुख अंतर्वाह के कारण 2013-14 में पूरे वर्ष की अपेक्षा उच्चतर रहा। (सारणी 7.3)

भारत का सेवा व्यापार

7.14 व्यावसायिक सेवाओं के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2000 में 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 2013 में 3.2 प्रतिशत हो गई है। 2013 में अग्रणी निर्यातकों में इसका

छठा स्थान है। 2002-03 से 2008-09 के 31.2 प्रतिशत की उच्च वृद्धि और वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के प्रभाव में 2010-11 और 2011-12 में रफ्तार पकड़ने एवं अच्छी वृद्धि देखने के बाद सेवा की निर्यात वृद्धि गिर कर 2012-13 में 3.4 प्रतिशत रह गई थी 2013-14 में सेवाओं के निर्यात में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 151.5 प्रतिशत बिलियन अमेरिकी डालर हो गया और सेवाओं के निर्यात में 2.8 प्रतिशत की गिरावट आने से यह 78.5 प्रतिशत बिलियन अमेरिकी डालर हो गया जिससे निवल सेवाएं 73.0 बिलियन हो गईं जो 12.4 प्रतिशत वृद्धि है। 2014-15 के पूर्वार्ध में, सेवा निर्यात 3.7 प्रतिशत बढ़कर 75.9 बिलियन अमेरिकी डालर और सेवा आयात 5 प्रतिशत बढ़कर 39.9 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया जिसके परिणामतः निवल सेवाओं में महज 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी 7.4)। हाल ही के वर्षों में निवल सेवाएं, भारत के व्यापार घाटे को पूरा करने का मुख्य स्रोत रही हैं। वित्तीय सेवाओं के अधिशेष से 2013-14 में और 2014-15 की पहली तिमाही में क्रमशः 49.4 प्रतिशत और 49.3 प्रतिशत जीस व्यापार घाटा पूरा किया गया है। भारत के निर्यात क्षेत्रों में हाल ही में हुए दो घटनाक्रम बढ़ती व्यापार मूल्य वर्धित घटक और सेवा मूल्य वर्धित घटक है (बॉक्स 7.1)।

7.15 2013-14 में भारत के प्रमुख सेवा निर्यात कंप्यूटर (45.8 प्रतिशत हिस्सा), पेशेवर और परामर्श सेवाओं (10.2 प्रतिशत) सहित व्यावसायिक तथा अन्य सेवाएं (18.8 प्रतिशत) हिस्सा और तकनीकी व व्यापार से संबंधित सेवाएं (10.2 प्रतिशत हिस्सा) अनुसंधान और

सारणी 7.4: प्रमुख सेवाओं में निर्यात का निष्पादन

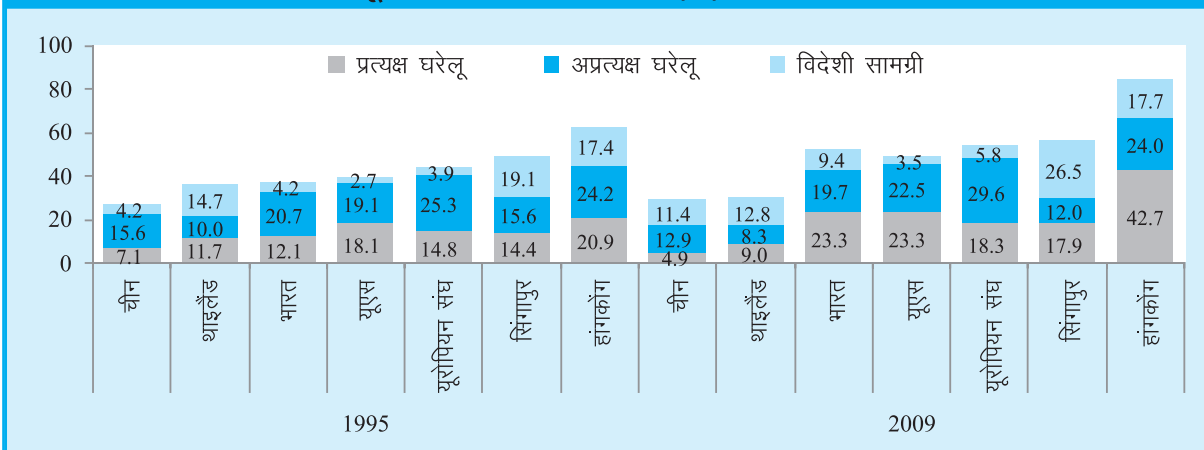
	मूल्य (यूएस बिलियन में) 2013-14	हिस्सा (प्रतिशत) 2013-14	निर्यात वृद्धि दर (प्रतिशत)			
			2012-13	2013-14	2013-14 H1	2014-15 H1
कुल सेवा निर्यात	151.5	100	3.4	4.0	3.4	3.7
परिवहन	17.4	11.5	-5.1	0.3	-2.1	8.5
यात्रा	17.9	11.8	-2.5	-0.4	4.8	18.0
निर्माण	1.3	0.9	24.9	33.3	37.2	36.0
वित्तीय, बीमा और पेंशन सेवाएं	8.8	5.8	-16.5	22.2	23.3	-11.8
दूरसंचार सेवाएं	2.4	1.6	2.0	43.0	38.4	-22.2
कंप्यूटर सेवाएं	69.4	45.8	5.9	5.4	5.6	5.1
अन्य व्यवसाय सेवाएं	28.5	18.8	15.8	0.1	-0.1	-3.9
अनुसंधान और विकास सेवाएं	1.1	0.8	17.0	24.0	9.7	6.3
पेशेवर और परामर्श सेवाएं	15.5	10.2	26.0	10.4	7.1	-6.7
तकनीकी, व्यापार संबंधी व अन्य	11.8	7.8	6.8	-12.2	-8.6	-1.4
निवल सेवा निर्यात	73.0	—	1.4	12.4	12.6	2.4

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान संतुलन संबंधी आंकड़े

बॉक्स 7.1 : भारत के निर्यात में सेवा सकल मूल्य वृद्धि घटक

ओईसीडी के मूल्य वर्धित व्यापार के आंकड़ों के अनुसार, भारत के सकल निर्यातों में घरेलू मूल्य वर्धित घटक 2009 में 78 प्रतिशत था, जो ओईसीडी के औसत (76 प्रतिशत) से थोड़ा अधिक किंतु 1995 की अपेक्षा 12 बिंदु (पीपी) कमतर है। जो वैश्विक मूल्य वृद्धि श्रृंखलाओं के साथ उत्पादन और एकीकरण में बढ़ते विखंडन को दर्शाता है। दिलचस्प है कि 2009 में भारत के निर्यात कर सेवा मूल्य वर्धित घटक 52.4 प्रतिशत है जो ओईसीडी के औसत (48 प्रतिशत) से कुछ अधिक है। भारत का अपने निर्यातों में सेवाओं में मूल्य वर्धित घटकों के मायने में हांगकांग, आइसलैण्ड, सिंगापुर और इयू-27 के बाद पांचवा स्थान है। इसमें 1995 की तुलना में 15.4 प्रतिशत पीपी की वृद्धि भी है (चित्र 1)। यह सेवाओं के बढ़ते प्रत्यक्ष निर्यात द्वारा प्रेरित है और निर्यात के विदेशी सेवा घटक के दोगुने से भी अधिक होने से वैश्विक मूल्य श्रृंखला की अधिक एकीकरण का संकेत मिलता है।

चित्र 1: सकल निर्यात के मूल्ययोजित सामग्री सेवाएं (%)



आईसीआरआईआईआर द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया अध्ययन भारत के निर्यातों में विदेशी मूल्य वृद्धि की बढ़ती हिस्सेदारी को दर्शाता है। यह बढ़ोत्तरी 1995 के जीएस निर्यात में 11.2 प्रतिशत से 2011 में अधिक 25.7 प्रतिशत थी जबकि सेवा निर्यात में यह 6.4 प्रतिशत से बढ़कर 8.5 प्रतिशत हो गयी।

स्रोत : ओईसीडी और आईसीआरआईआईआर की रिपोर्ट पर आधारित

विकास सेवाएं (0.8 प्रतिशत), यात्रा (11.8 प्रतिशत) और परिवहन (11.5 प्रतिशत हिस्सा) और वित्तीय, बीमा एवं पेंशन सेवाएं (5.8 प्रतिशत हिस्सा) हैं। 2013-14 में, सॉफ्टवेयर सेवाओं की निर्यात वृद्धि में 5.4 प्रतिशत की गिरावट, यात्रा में (-)0.4 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि, परिवहन (0.3 प्रतिशत) और अन्य व्यावसायिक सेवाओं (0.1 प्रतिशत) में मामूली वृद्धि थी। तथापि, वित्तीय सेवाओं के वैश्विक निर्यातों के साथ तालमेल में, भारत की वित्तीय सेवाओं के निर्यात में 34.4 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर्ज हुई है। 2014-15 की पहली छमाही में, निर्यात वृद्धि में कंप्यूटर सेवाओं में और अधिक गिरावट आई (5.1 प्रतिशत) और अन्य व्यावसायिक सेवाओं (-3.9 प्रतिशत) और वित्तीय, बीमा और पेंशन सेवाओं (-11.8 प्रतिशत) में यह ऋणात्मक थी। लेकिन यात्रा में मजबूत वृद्धि (18.0 प्रतिशत) थी और

विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए और विदेशी विनिमय आय (एफईई) के डालर के मायने में रफ्तार पकड़ी। और पिछले पूर्व वर्ष में 0.8 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 की पहली तिमाही में भारत के विदेशी व्यापार में 2.5 प्रतिशत की तेजी के कारण परिवहन के लिए अच्छा संकेत रहा (8.5 प्रतिशत)।

7.16 भारत के सेवा क्षेत्र में बाजार तक पहुंचने में बहुत से अवरोधक और घरेलू नियम हैं (देखें आर्थिक सर्वे 2012-13 और 2013-14)। भारत की सेवा क्षेत्र की संभावना को देखते हुए, इन दोनों ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अवरोधों को दूर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः बहुपक्षीय और द्विपक्षीय/क्षेत्रीय अर्थात् दोनों ही स्तरों पर सेवा क्षेत्र में बातचीत किया जाना भारत के लिए विशेष महत्व रखता है। (देखें बाक्स 7.2)

बाक्स 7.2 : द्विपक्षीय समझौता वार्ताएं, सेवा व्यापार सहित विश्व व्यापार संगठन वार्तालाप

विश्व व्यापार संगठन : भारतीय स्थिति

- बाली बातचीत के पश्चात् जो भी कार्यक्रम तैयार होगा उसे दोहा डेवलपमेंट (डीडीए) के परमादेश के भीतर ही तैयार किया जायेगा और हांगकांग मिनीस्टीरियल डिक्लरेशन (एचकेएमडी) की सेवा संबंधी अनुबंध ग जैसे महत्वपूर्ण कदमों, जिसमें दोहा दौर की वार्ता का मार्गदर्शन भी शामिल है, के मद्देनजर भी तैयार किया जायेगा।
- भारत दोहा दौर की वार्ता के नाम पर छोटे मोटे लाभ और कतिपय अर्थव्यवस्थाओं के हित क्षेत्रों का समर्थन नहीं करता है और वार्तालाप के सभी स्तम्भों जिसमें महत्वाकांक्षा का स्तर भी शामिल है, पर कृषि को ही प्रधानता दी जायेगी।
- चूंकि दोहा वार्तालाप का केन्द्र बिन्दु विकास है अतः विकासशील और अल्पमत विकसित देशों के निर्यात हितों के क्षेत्र में प्रतिबद्धता इस दौर की सफलता के लिए खास महत्व रखते हैं। विगत में मोड 4 आफर्स में जो नगण्य प्रगति हुई है उससे भारत हताश हो गया है।
- डब्ल्यू.टी.ओ. में अल्पमत विकसित देशों को विशेष वरीयता देने के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन्स को दी जाने वाली छूट- 5 फरवरी 2015 को होने वाली डब्ल्यू.टी.ओ. सेवा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक में अल्पमत विकसित राज्यों के लिए छूट दिये जाने के मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ था। भारत अल्पमत विकसित देशों के लिए एक उदार सहभागी बना रहा है और इसने अनुबंधित सेवा प्रदाताओं और स्वतंत्र व्यवसायिकों (मोड 4) को इंजीनियरिंग सेवा, कंप्यूटर और इससे संबंधित सेवा तथा प्रबंधन और परामर्श सेवा में बाजार मुहैया कराया है। अल्पमत विकसित देशों से पर्यटन मार्गदर्शकों के लिए केवल 250 कोटा दिया गया था। भारत इन देशों के उन आवेदकों को वीजा शुल्क माफ करने पर सहमत हो गया है जो भारत में व्यापार या रोजगार के लिए वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं।

द्विपक्षीय करार: स्थिति

- भारत ने सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान और मलेशिया के साथ वृहद् द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किये हैं। एशियान देशों के साथ सेवा और निवेश के क्षेत्र में सितम्बर 2014 में एफटीए पर हस्ताक्षर किये गये थे।
- भारत एक बहुपक्षीय वार्तालाप रिजनल कम्प्रोमिस्स इकोनामिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) में शामिल हो गया है और कनाडा, इजराइल, थाईलैण्ड, ईएफटीए आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपीय समुदाय के साथ व्यापार सेवा के क्षेत्र में द्विपक्षीय एफटीए वार्तालाप में लगातार संलग्न है। थाईलैण्ड के साथ वार्तालाप काफी आगे तक हो गया है और ईएफटीए के साथ होने वाला वार्तालाप कर्मादेश पूरा हो गया है। भारत इण्डिया-यूएस ट्रेड पालिसी फोरम (टीपीएफ) के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, इण्डिया-आस्ट्रेलिया ज्वाइंट मिनिस्टीरियल कमीशन (जेएमसी) के अंतर्गत आस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया-चाइना वर्किंग ग्रुप आन सर्विसेज के अंतर्गत चीन के साथ और इण्डिया ब्राजील ट्रेड मानीटरिंग मेकेनिज्म (टीएमएम) के अंतर्गत ब्राजील के साथ भी द्विपक्षीय व्यापार वार्तालाप के कार्य में लगा हुआ है।

स्रोत: वाणिज्य विभाग, भारत सरकार

सारणी 7.5: क्षेत्रवार रोजगार का रुख (यूपीएस)

	समग्र संख्या (मिलियन) (प्रतिशत का हिस्सा कोष्ठक में दिया गया है)					रोजगार में लोच			
	1993-94	1999-00	2004-05	2009-10	2011-12	1993-94 से 1999-00	1999-00 से 2004-05	2004-05 से 2009-10	2009-10 से 2011-12
	कृषि	204.3 (61.1)	214.7 (58.5)	226.8 (54.5)	220.5 (51.6)	204.4 (47.1)	0.3	0.7	-0.2
उद्योग	53.5 (16.0)	61.7 (16.8)	81.0 (19.5)	93.1 (21.8)	106.1 (24.4)	0.4	0.9	0.3	0.9
सेवा	76.6 (22.9)	90.6 (24.7)	108.0 (26.0)	113.7 (26.6)	123.9 (28.5)	0.3	0.5	0.1	0.5
व्यापार, होटल और रेस्तरां	26.8 (8.0)	34.1 (9.3)	46.5 (11.2)	48.4 (11.3)	50.5 (11.6)	0.4	0.8	0.1	0.3
परिवहन, भंडारण व संप्रेषण	11.0 (3.3)	15.0 (4.1)	18.7 (4.5)	19.9 (4.6)	22.8 (5.2)	0.5	0.4	0.1	0.6
वित्तीय बीमा, भू-संपदा और व्यवसाय सेवाएं	3.7 (1.1)	4.8 (1.3)	7.5 (1.8)	9.4 (2.2)	10.7 (2.5)	0.5	1.6	0.4	0.6
समुदाय, सामाजिक और निजी सेवाएं	35.1 (10.5)	36.7 (10.0)	35.3 (8.5)	36.1 (8.4)	39.9 (9.2)	0.1	-0.2	0.1	1.1
कुल	334.4 (100.0)	367.0 (100.0)	415.7 (100.0)	427.4 (100.0)	434.4 (100.0)	0.2	0.4	0.1	0.1

स्रोत : एनएसएसओ की विभिन्न दौर की रिपोर्टों और सीएसओ से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित

नोट : रोजगार लचीलापन की गणना सीएजीआर विधि से की जाती है। संबंधित अवधि का रोजगार लचीलापन = (सीएजीआर रोजगार)/(एफसी स्थिर 2004-05 मूल्य पर सीएजीआर जीडीपी। यू.पी.एस.- युजुअल प्रिंसीपल स्टेटस

भारतीय सेवा रोजगार

7.17 पिछले दो दशकों में रोजगार के क्षेत्रवार प्रतिमान में बदलाव आया है और कृषि के क्षेत्र में रोजगार में कमी आयी तथा उद्योग एवं सेवा के क्षेत्र में रोजगार काफी तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2011-12 में रोजगार में सेवा का हिस्सा 28.5 प्रतिशत प्रतिशत रहा है जो कि उद्योग (24.4 प्रतिशत) क्षेत्र के रोजगार से अधिक है। सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में, वर्ष 1993-94 से 2011-12 के बीच व्यापार, होटल एवं रेस्तरां, परिवहन, स्टोरेज, संचार और वित्त बीमा, सम्पदा और व्यापार सेवाओं में रोजगार के हिस्से में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है। सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवाओं में रोजगार के हिस्से में वर्ष 2011-12 को छोड़कर लगातार कमी आयी है फिर भी 2009-10 और 2004-05 की तुलना में वृद्धि हुई है। वर्ष 2004-05 से 2009-10 की तुलना में वर्ष 2009-10 से 2011-12 में रोजगार में लचीलापन बढ़ा है, यद्यपि उद्योग के क्षेत्र में यह लचीलापन तुलनात्मक रूप से अधिक रहा है। सेवाओं में रोजगार का लचीलापन वित्त, बीमा, सम्पदा और व्यापार

सेवा तथा परिवहन, भण्डारण और संचार के क्षेत्र में अधिक रहा है। (सारणी 7.5)

प्रमुख सेवायें: समग्र निष्पादन

7.18 वर्ष 2014-15 के भारत की विभिन्न सेवाओं के बारे में उपलब्ध कुछ संकेतकों से पता चलता है कि पर्यटन, दूर संचार, विमानन और रेलवे का कामकाज ठीक ठाक रहा है (सारणी 7.6)। लिमिटेड फर्मों के स्तर पर सेंटर फार मानीटरिंग इण्डियन इकोनामी के द्वारा लगाये गये अनुमानों से पता चलता है कि खुदरा व्यापार, विमानन, दूर संचार, और परिवहन लाजिस्टिक्स के कामकाज में सुधार आया है। अन्य अनुमानों जैसे एचएसबीसी की सेवायें, पीएमआई (पर्जेंचिंग मैनेजर्स इन्डेक्स) के आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वर्ष में सेवा-क्षेत्र में सुधार आया है क्योंकि मई 2014 से लेकर सभी महीनों में रीडिंग 50 से ऊपर रही है और यह नवम्बर 2014 में 52.6, दिसम्बर 2014 में 51.1 तथा जनवरी 2015 में 52.4 रही है।

सारणी 7.6 : भारत के सेवाक्षेत्र का निष्पादन: कुछेक संकेतक

क्षेत्र	संकेतक	ईकाई	अवधि		
			2009-10	2013-14	2014-15
विमानन	एअर लाइन्स के यात्री (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय)*	मिलियन	77.4	103.7	(68.0)74.9 [#]
दूर संचार	(दूर संचार कनेक्शन्स वायर लाइन और वायरलेस) ^{##}	मिलियन	621.3	933.0	(910.1)964.2 [#]
पर्यटन	विदेशी पर्यटकों का आगमन ^{##}	मिलियन	5.2	7.0	7.5
	विदेशी पर्यटकों से विदेशी मुद्रा का अर्जन ^{##}	बिलियन अमरीकी डालर	11.1	18.4	19.7
जहाजरानी	भारतीय जहाजरानी का सकल टनेज ^{##}	मिलियन जीटी	9.7	10.5	10.3 [@]
	जहाजों की सं. ^{##}	संख्या	1003	1213	1209 [@]
पत्तन	पत्तन यातायात	मिलियन टन	850.0	975.7	(725.9)775.2 [@]
रेलवे	रेलवे द्वारा माल परिवहन ^{##}	मिलियन टन	887.8	1051.6	(767.2)806.4 [@]
	रेलवे का निवल टन किलोमीटर्स ^{##}	बिलियन	600.5	665.8	(478.9)506.9 [@]
भण्डारण	भण्डारण क्षमता	लाख एमटी	106.0	105.6	103.1 [#]
	भण्डारगाहों की संख्या	संख्या	487	471	470 [#]

स्रोत : टीआएआई, पर्यटन मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, नागरिक विमानन मंत्रालय, सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन

टिप्पणी : ^{##}कलेण्डर वर्ष जैसे कि 2009 के लिए 2009-10; ^{##}आने वाले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को 2009-10 से 2012-13 के आंकड़े अग्रसरित आधार पर हैं जबकि 2013-14 के आंकड़े मूल आधार पर हैं; ^{##}विदेशी एअर लाइन्स (विदेशी यात्रियों के लिए शामिल), जबकि 2013-14 और 2014-15 के लिए उद्भूत आधार पर हैं; * विदेशी एयर लाइन्स में अंतर्राष्ट्रीय यात्री शामिल हैं; [#] आंकड़े नवंबर, 2014 तक हैं [@] आंकड़े दिसम्बर, 2014 तक हैं कोष्ठक में आंकड़े 2013-14 की समान अवधि के लिए हैं जीटी = सकल टनेज एमटी = मीट्रिक टन.

प्रमुख सेवायें: क्षेत्रवार निष्पादन और कुछ सामयिक नीतियां

7.19 इस खण्ड में भारत की कुछ प्रमुख वाणिज्यिक सेवाओं को शामिल किया गया है जो कि जीडीपी, रोजगार, निर्यात, और भावी दृष्टि से काफी महत्व रखती हैं। अन्य अध्यायों में जिन प्रमुख सेवाओं का उल्लेख किया गया है उनको यहां छोड़ दिया गया है ताकि दोहरापन से बचा जा सके।

पर्यटन

7.20 विश्व व्यापार एवं पर्यटन परिषद (डब्ल्यूटीटीसी) के अनुसार, विश्व की जीडीपी में संयुक्त राज्य के परिवहन एवं पर्यटन क्षेत्र का जो 7 ट्रिलियन अमेरिकी डालर का योगदान है, वह 2013 में बढ़कर विश्व जीडीपी का 9.5 प्रतिशत हो गया है और इसमें 4.7 मिलियन नई नौकरियों का सृजन हुआ है। इससे इस क्षेत्र में कुछ रोजगार लगभग 266 मिलियन हो गया है जो कि विश्व की 11 नौकरी के हिसाब से 1 नौकरी है। इस क्षेत्र में 2014 तक 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है और 6.5 मिलियन नई नौकरियों पैदा हो सकती हैं। संयुक्त विश्व पर्यटन संगठन के नवीनतम विश्व पर्यटन बैरोमीटर से पता चलता है कि 2014 में 1.2 बिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों

का आगमन हुआ था जोकि पिछले वर्ष मुकाबले 4.7 प्रतिशत अधिक है और वर्ष 2015 में इसमें 3 से 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होने का पूर्वानुमान किया गया है। 2013 में विश्व के एफटीए में फ्रांस का और एफईआर में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे अधिक हिस्सा रहा है। विश्व एफटीए में भारत का हिस्सा 6.4 प्रतिशत रहा है जोकि फ्रांस के 7.8 प्रतिशत और संयुक्त राज्य अमेरिका के 6.4 प्रतिशत के लगभग बराबर ही है। यहां तक कि वियतनाम और इण्डोनेशिया का हिस्सा भारत से ज्यादा है। हालांकि, एफईआर की दृष्टि से भारत का जो 1.5 प्रतिशत का हिस्सा है वह वियतनाम और इण्डोनेशिया से बेहतर है हालांकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के 14.5 प्रतिशत से बहुत कम है। यहां तक विकास की दृष्टि से भी 2013 में वियतनाम, इण्डोनेशिया, थाईलैण्ड और तुर्की जैसे देश भी भारत से आगे रहे हैं। सारणी (7.7)

7.21 भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में पर्यटन के लिए कोई अलग शीर्ष नहीं रखा गया है। पर्यटन संबंधी क्रियाकलापों के कुछ हिस्से जैसे ट्रेवल एजेंट टूर आपरेटर और अन्य आरक्षण परक कार्य “प्रशासनिक एवं समर्थन सेवा क्रियाकलाप का ही हिस्सा है। दूसरे टूरिज्म एकाउण्ट्स ऑफ इण्डिया (टीएसए) के अनुसार, 2012-13 के दौरान कुल जीडीपी में

सारणी 7.7 : पर्यटन में प्रगति अंतर्राष्ट्रीय तुलना - 2013 के दौरान

देश	अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन			अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियां		
	संख्या (मिलियन में)	हिस्सा (%)	वृद्धि(%)	मूल्य (बिलियन अमेरीकी डालर)	हिस्सा (%)	वृद्धि (%)
फ्रांस	84.7	7.8	2.0	56.7	4.7	5.6
यूएस	69.8	6.4	4.7	173.1	14.5	7.4
स्पेन	60.7	5.6	5.6	60.4	5.1	7.3
टर्की	37.8	3.5	5.9	28.0	2.3	10.7
थाइलैंड	26.5	2.4	18.8	42.1	3.5	24.6
मलेशिया	25.7	2.4	2.7	21.5	1.8	6.4
सिंगापुर	11.9	1.1	7.2	19.1	1.6	1.1
इंडोनेशिया	8.8	0.8	9.4	9.1	0.8	9.5
वियतनाम	7.6	0.7	10.6	7.5	0.6	10.3
भारत	6.8	0.6	4.1	18.4	1.5	4.0
विश्व	1087	100.0	4.8	1195	100.0	7.2

स्रोत : संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन

पर्यटन का योगदान 6.9 प्रतिशत (3.7 प्रतिशत प्रत्यक्ष और 3.1 प्रतिशत अप्रत्यक्ष) रहा है और कुल रोजगार में इसका योगदान 12.4 प्रतिशत (5.3 प्रतिशत प्रत्यक्ष और 7.0 प्रतिशत अप्रत्यक्ष) रहा है। वर्ष 2013 विदेशी पर्यटनों के आगमन में 5.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने के बावजूद विदेशी मुद्रा के अर्जन की स्थिति, जोकि डालर की दृष्टि से 4.0 प्रतिशत रही है, अच्छी नहीं रही है; वहीं दूसरी ओर वर्ष 2014 में एफटीए (7.1 प्रतिशत) और एफईई (6.6) दोनों में ही वृद्धि हुई है।

7.22 वर्ष 2014-15 के बजट में, सरकार ने पर्यटन पर जोर देने के अपने इरादे को और सेवाकर के अवरोध को दूर करने, गंगा नदी विश्व स्तरीय बुद्धिस्ट सर्किट के विकास और विश्व स्तरीय अध्यात्मिक स्तर बनाने जैसे कई प्रयास शुरू किए हैं। इस इरादे को पुनः क्रियान्वित करने के लिए पर्यटन वीजा को सरल बनाया गया है जिसके तहत 43 देशों के लिए आगमन पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवेल आथराइजेशन के द्वारा पर्यटन वीजा दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

परिवहन संबंधी कुछ सेवाएं

पोत परिवहन

7.23 जहाजरानी किसी भी देश की वस्तु एवं सेवा दोनों का ही एक प्रमुख संकेतक होता है भारत का व्यापार की प्रमात्रा के सन्दर्भ में 95 प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से 68 प्रतिशत समुद्र के रास्ते होता है। 31 दिसम्बर, 2014 के अनुसार, भारत के पास 1,209 जहाजों का बेड़ा था जिसकी सकल टनेज 10.3 मिलियन था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय

पोत परिवहन निगम का हिस्सा लगभग 31 प्रतिशत का है। इनमें से 358 जहाज, जिनका कुल टनेज 9.1 मिलियन है, समुद्र-पारीय व्यापार की जरूरतों को पूरा करते हैं जबकि बाकी जहाज समुद्रतटीय व्यापार की जरूरतें पूरी करते हैं। विकासशील देशों में जहाजों का सबसे बड़ा बेड़ा रखने के बावजूद 1 जनवरी, 2014 की स्थिति के अनुसार विश्व के कुल डीडब्ल्यूटी व्यापार में भारत का हिस्सा मात्र 1.1 प्रतिशत का रहा है। वर्ष 2013 में, यूएनसीटीएडी के अनुसार, भारत जिसकी 10.7 मिलियन ट्वेन्टी फूट इक्विटिलेण्ट यूनिट्स आफ कन्टेनर की और विश्व व्यापार में जिसका हिस्सा 1.6 प्रतिशत था, कन्टेनर-शिप आपरेशन्स की दृष्टि से विकासशील देशों में इसका आठवां स्थान आता है।

7.24 जहाजों के भंजन कार्य में भारत विश्व का अग्रणी देश बना हुआ है। वर्ष 2014 (जनवरी से अक्टूबर) में जहाज की रिसाइक्लिंग करने वाले देशों में भारत का स्थान शीर्षस्थ रहा है और आईएसएल शिपिंग स्टेटिस्टिक्स एण्ड मार्केट रिव्यू के अनुसार विश्व में इसका हिस्सा 32 प्रतिशत का रहा है। इसका भंजन कार्य 234 जहाजों का है जिनका कुल टनेज 7.98 मिलियन डीडब्ल्यूटी होता है। भारत विश्व में सीफेयरर का एक बहुत बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। बीआईएमसीओ/आईएसएफ मैन पावर अपडेट 2010-14 के अनुसार, भारत ने 2014 में 60,000 चालक (फ्रेश सी मेन) और 44,500 अधिकारी उपलब्ध कराये हैं।

7.25 वर्ष 2008 से पोत परिवहन क्षेत्र को आर्थिक कड़िनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 2014 में पोत परिवहन के सभी

सारणी 7.8 : भारत में पत्तनों के कुछ प्रदर्शन संकेतक

संकेतक	(अप्रैल-नव.)				
	2000-01	2010-11	2012-13	2013-14	2014-15
औसत आमूल परिवर्तन समय (दिन)	4.2	2.7	2.6(0.0)	2.3(-0.3)	2.1(-0.1)
औसत प्री बर्थ समय (दिन)	1.2	0.5	0.5(0.0)	0.3(-0.2)	0.2(-0.1)
औसत आउटपुट प्रति जहाज दिन (टन में)	6961	9140	11786(-1287)	12509(723)	14326(1817)

स्रोत : जहाजरानी मंत्रालय

टिप्पणी : विगत वर्षों से परिवर्तन कोष्ठक में दिए गए हैं।

अवयवों में रुक-रुक कर अड़चने आई हैं लेकिन इनमें से किसी में भी स्थिति बदतर नहीं हुई है। इसके अलावा, 2015 में नये जहाजों के अंतर्राष्ट्रीय डिलीवरी में गिरावट आई है जिससे जहाज के किराया की दरों में भी कमी आ सकती है। वाल्टिक इन्डेक्स, जोकि मकेन्डइण्ड ट्रेड और शिपिंग सेवाओं का एक बैरोमीटर है और 20 मई 2008 को अपने चरम शिखर अर्थात् 11,793 पर था तब से नीचे आ गया है और 6 फरवरी 2015 को यह 530 हो गया था।

7.26 भारत के समुद्रपारीय व्यापार के परिवहन में भारतीय जहाजों का हिस्सा जो 1980 के दशक में 40 प्रतिशत था घटकर 2012-13 में 9.1 प्रतिशत तक आ गया था। भारतीय बेड़ा पुराना भी पड़ता जा रहा है। और भारतीय बेड़े की औसत आयु 1999 के 15 वर्ष से बढ़कर 1 अक्टूबर, 2014 को 17.7 हो गया है (43.1 प्रतिशत बेड़े 20 वर्ष पुराने और 10.7 प्रतिशत 16-19 वर्ष आयु समूह के हैं। इस प्रकार भारत के जहाजी बेड़े को बढ़ाने की सख्त आवश्यकता है।

7.27 भारतीय टनेज को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता को समझते हुए कई नीतिगत कदम उठाये गये हैं जिनमें भारतीय शिपिंग कंपनियों को बाहर से जहाज खरीदने और अपने सुविधा के अनुसार इस देश में चलाने के लिए अनुमति देना, बाहर से सस्ते दर पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने, निर्यात और आयात मर्चों के परिवहन के लिए भारतीय फ्लेग वाले जलयानों में प्रयोग होने वाले बंकर फ्यूएल पर तथा भारत में दो बन्दरगाहों के बीच चलने वाले खाली कन्टेनरों पर सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादशुल्क से छूट प्रदान करना है; और जहाज मरम्मत ईकाईयों के लिए डाइरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के यहां पंजीकरण कराने की जो शर्त है उससे छूट दिया जाना भी शामिल है।

पत्तन सेवा

7.28 भारतीय बन्दरगाहों से होने वाला कार्गो यातायात 4.5 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में 975.7 मिलियन टन हो

गया है और यह (अप्रैल-दि.) 2014-15 में 6.8 प्रतिशत बढ़ गया है। मैरीटाइम एजेन्डा में, वर्ष 2020 तक के लिए 3130 मीट्रिक टन पोर्ट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 296,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की जरूरत पड़ेगी। इस क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक भाग छोटे पत्तनों पर सृजित किया जायेगा। बन्दरगाहों के निर्माण और रख-रखाव के लिए स्वचालित रूट के तहत 100 प्रतिशत तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। 2013-14 में मुख्य बंदरगाहों में 159.7 एमटी की अतिरिक्त क्षमता के लिए 18640.8 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 16 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाएं प्रदान की गई थी, जिसमें बर्थ, टर्मिनल का निर्माण और मौजूदा बर्थ का यंत्रीकरण शामिल है।

7.29 तीन बंदरगाह संबंधी कार्य निष्पादन के संकेतकों में औसत आमूल परिवर्तन समय से सुधार बना रहा और पूर्व बर्थ डिटेंशन समय में क्रमशः 2.1 दिन और 0.2 प्रतिशत दिन की गिरावट आई और औसत आउटपुट में 2014-15 (अप्रैल-नवम्बर) में 14,326 टन का सुधार आया। (सारणी 7.8)। आमूल परिवर्तन समय और पूर्व बर्थ डिटेंशन समय में सुधार आंशिक तौर पर बंदरगाहों में मशीनीकरण और व्यवस्थागत सुधार के कारण और आंशिक तौर पर, वैश्विक मंदी की वजह से कुछ बंदरगाहों का परिमाण में निपटान की वजह से है। तथापि, औसत आउटपुट प्रति जहाज प्रति दिन में सुधार से संकेत मिलता है कि भारतीय बंदरगाहों के कार्य निष्पादन के पैरामीटरों में भी सुधार आया है।

कुछ व्यावसायिक सेवाएं

सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं

7.30 सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और नालेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसिज भारत की अर्थव्यवस्था में गतिशील और जीवंत क्षेत्र के

रूप में उभरकर सामने आए हैं। एटी कीयरनी ग्लोबल सर्विस लोकेशन इण्डेक्स 2014 के अनुसार, तटवर्ती सेवाओं में भारत का प्रथम स्थान है और यह पूर्व निर्धारित स्थान बना हुआ है एवं आईटी, वीपीओ एवं वायस सेवाओं में यह शीर्ष स्थान पर था। सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों के राष्ट्रीय संघ के अनुसार, इस क्षेत्र में 3.5 मिलियन लोग कार्यरत हैं।

7.31 केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसार, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 3.3 प्रतिशत हिस्से के साथ कम्प्यूटर और संबंधित सेवाओं 2013-14 में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नास्कॉम के अनुसार 2014-15 में आईटी-बीपीएम उद्योग में 119 मिलियन, अर्थात् 12.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि निर्यात बाजार में पूर्व वर्ष की अपेक्षा 98 बिलियन अमरीकी डॉलर, 12.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बीपीएम क्षेत्र हितकारी स्रोतों की मौजूदगी और पूरी मूल्य शृंखला में गतिकी के प्रयोग, बेहतर स्वचालन से प्रेरित है। इस वर्ष तकनीकी प्रयोग और सॉफ्टवेयर उत्पाद में भरपूर बढ़ोतरी देखी गई जिससे भारत, देश में 3100 से अधिक स्टार्ट अप के साथ विश्व में चौथा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप केन्द्र बन गया है। घरेलू आईटी-बीपीएम बाजार 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ 2014-15 में 20.9 मिलियन अमरीकी डालर अनुमानित है। नॉसकाम के अनुसार 2015-16 में सॉफ्टवेयर उत्पाद और सेवा राजस्व में 12-14 प्रतिशत की वृद्धि से 113-136 बिलियन अमरीकी डालर रहने का अनुमान है। 2015-16 के दौरान निर्यात राजस्व में 12-14 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 110-112 बिलियन अमरीकी डालर और घरेलू राजस्व के 10-15 प्रतिशत वृद्धि के साथ 23-24 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचने के अनुमान है।

7.32 अपने देश में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की और अधिक आवश्यकता को महसूस करते हुए, बजट 2014-15 में भारत को ज्ञान पर आधारित परिवर्तन के लिए तैयार करने के लिए डिजिटल भारत को एक महत्वाकांक्षी अम्ब्रेला प्रोग्राम के रूप में देखा जा रहा है। यह ग्रामीण स्तर पर ब्रोड-बैंड संबद्धता, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित मंच के द्वारा सेवाओं तक पहुंचने, सरकारी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के स्वदेशी उत्पादन का एक मुख्य घटक आधार प्रमाणन मंच के साथ युग्मित क्लाउड आधारित पात्रता

की उपलब्धता के जरिये जनता का सशक्तीकरण है। सरकारी सेवा वितरण के लिए ई-क्रांति अन्य पहल है। सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को पहचानते हुए 25 फोकस क्षेत्रों में, भारत के “मेक इन इंडिया” मिशन में सूचना प्रौद्योगिकी और व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन शामिल किए गए हैं।

अनुसंधान और विकास सेवाएं

7.33 अनुसंधान और विकास क्षेत्र में 2012-13 में 20.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लगातार दोगुने आंकड़े के स्तर से वृद्धि हो रही है। व्यावसायिक, वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियां और अनुसंधान और विकास में 2013-14 में 14.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जिनोव प्रबंधक परामर्शी, “वैश्विक अनुसंधान और विकास सेवा प्रबंधक रेटिंग 2014” की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का अनुसंधान और विकास, वैश्वीकरण और सेवाएं बाजार 2020 में दोगुना, यानी 38 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा। यह अध्ययन 2014 की स्थिति के अनुसार 170 बिलियन अमरीकी डालर पर समग्र ध्यान दिए जाने योग्य अनुसंधान और विकास वैश्वीकरण और सेवा के अवसरों का अनुमान है। वर्तमान में, वैश्विक स्तर पर इसमें केवल 55 बिलियन अमरीकी डालर की हिस्सेदारी है। इस बाजार में भारत की हिस्सेदारी 33 फीसदी है जिसमें इन-हाउस केन्द्रों का अपनी मूल कंपनियों की सेवाओं में 11.3 बिलियन अमरीकी डालर का योगदान है।

7.34 वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार, भारत की नवोत्पाद के लिए क्षमता अमेरिका, इंग्लैंड, साउथ कोरिया और यहां तक कि अन्य ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका) (सारणी 7.9) जैसे देशों से भी कम रही है। वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं की गुणवत्ताके मामले में भी भारत चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका से पीछे है। चीन और साउथ अफ्रीका जैसे ब्रिक्स राष्ट्रों की तुलना में अनुसंधान और विकास पर भारत में विश्वविद्यालय उद्योग सहयोग कम होने के माध्यम से भी यह प्रदर्शित होता है। जनसंख्या के प्रत्येक दस लाख पर दिए जाने वाले पेटेंट में भी भारत अन्य ब्रिक्स देशों से पीछे है। अनुसंधान और विकास पर कंपनी व्यय के मामले में भी भारत चीन से बहुत पीछे है। केवल वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उपलब्धता में भारत अन्य ब्रिक्स देशों से अच्छा है या उनके बराबर है।

सूची 7.9 : वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक अनुसंधान और विकास नवप्रवर्तन

देश	नवोत्पादन की क्षमता		वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों की गुणवत्ता		अनुसंधान और विकास पर कंपनी व्यय		अनुसंधान और विकास पर विश्वविद्यालय और उद्योग का सहयोग		वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उपलब्धता		प्रदान किए गए पीसीटी पेटेंट/दस लाख जनसंख्या	
	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक
अमेरिका	5.9	2	6.1	4	5.5	4	5.8	2	5.3	5	149.8	11
इंग्लैंड	5.3	10	6.3	2	4.8	14	5.7	4	4.8	22	89.1	18
साउथ कोरिया	4.7	24	5.0	27	4.5	20	4.6	26	4.4	42	201.5	8
साउथ अफ्रीका	4.3	35	4.7	34	3.4	48	4.5	31	3.5	102	6.5	45
चीन	4.2	40	4.3	39	4.3	23	4.4	32	4.4	43	11.7	34
ब्राजील	4.1	44	4.0	50	3.5	43	3.8	54	3.3	114	3.2	50
भारत	4.0	48	4.0	52	3.8	30	3.9	50	4.4	45	1.5	61
रूस	3.8	66	4.0	56	3.2	62	3.6	67	4.1	70	7.1	41

स्रोत : वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 23014-15, विश्व अर्थव्यवस्था मंच

नोट : पीसीटी-पेटेंट सहकारिता समझौता

परामर्शी सेवाएं

7.35 परामर्शी सेवाएं भारत में विभिन्न क्षेत्रों में सबसे तेजी से उभरती सेवाएं हैं और इनमें कुछ अतिव्यापन भी हो जाता है। प्लेक्ट रिसर्च के अनुसार वैश्विक परामर्शी उद्योग का राजस्व (एचआर, आईटी, स्ट्रेटिजी, प्रचालन, प्रबंध और कारोबारी सलाहकार संबंधी सेवाओं सहित) वर्ष 2014 में बढ़कर 431 बिलियन अमरीकी डॉलर के अनुमानित स्तर तक जा पहुंचा, जबकि पिछले वर्ष यह राजस्व 415 बिलियन अमरीकी डॉलर था। भारत का आउटसोर्सिंग और परामर्शी उद्योग वर्ष 2014 में 86.4 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है जो वैश्विक परामर्शी उद्योग के राजस्व का लगभग 20 प्रतिशत बैठता है, और इसके वर्ष 2015 में 99.0 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर पहुंचने की संभावना है।

7.36 विश्व स्तर पर तेजी से विकसित होते परामर्शी बाजार के रूप में भारत का उभरना मुख्यतः एफडीआई के उदारीकरण के कारण निवेश कार्यकलापों में हुई वृद्धि, भारतीय बाजार में कई नए कारोबारियों का आगमन और कम लागत की सोर्सिंग को कहा जा सकता है। भारतीय परामर्शदाताओं को इंजीनियरी परामर्श के क्षेत्र में विशेष रूप से विशेषज्ञता हासिल है जिसका लाभ परामर्शी निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाया जा सकता है।

स्थावर सम्पदा और आवास निर्माण

7.37 स्थावर सम्पदा और मकानों का स्वामित्व वर्ष 2013-14 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 7.8 प्रतिशत था। घरेलू और वैश्विक दोनों प्रकार की मंदी ने इस क्षेत्र को प्रभावित किया और इसका विकास वर्ष 2012-13 के 7.6 प्रतिशत से गिरकर 2013-14 में 6.0 प्रतिशत रह गया तथा स्थावर

सम्पदा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अप्रैल-2014 की अवधि में गिरकर 703 मिलियन अमरीकी डॉलर रह गया।

7.38 भारत में आवासीय मूल्यों के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक के रेजिडेक्स सूचकांक के अनुसार पिछले वर्षों में कई शहरों और नगरों में मकानों की कीमतों में वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 के दौरान 26 शहरों में से 17 शहरों में वर्ष 2013 की तुलना में कीमतों में वृद्धि देखी गई। अधिकतम वृद्धि चैन्नई (17 प्रतिशत) में देखी गई जिसके बाद अहमदाबाद (15 प्रतिशत) का स्थान रहा। जबकि पिछले वर्ष की तुलना में 7 शहरों में कीमतों में गिरावट देखी गई जहां अधिकतम गिरावट मेरठ (-16 प्रतिशत) में देखी गई जिसके बाद चंडीगढ़ (-8 प्रतिशत) का स्थान रहा।

7.39 मकानों की मांग और पूर्ति के बीच बढ़ता अंतराल तथा आवास-वित्त संबंधी अपर्याप्त साधन भारत के लिए एक प्रमुख नीतिगत सरोकार बना हुआ है। शहरी आवास की मौजूदा कमी 18.8 मिलियन यूनिट की है जिसमें से 95.6 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)। निम्न आय समूह (एलआईजी) से संबंधित है और इस कमी को पूरा करने के लिए बड़े वित्तीय निवेश की जरूरत है। हालांकि आवास निवेश के लिए संस्थागत ऋण लगभग 19 प्रतिशत प्रति वर्ष की सीएजीआर पर बढ़ने के बावजूद यह चीन, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों से काफी कम है। विश्व बैंक की, “डूईंग बिजनेस 2015” के अनुसार, निर्माण परमितों के संदर्भ में भारत का दर्जा (189 अर्थव्यवस्थाओं में से) 184वां था जहां परमित प्राप्त करने के लिए औसतन 27 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है जबकि दक्षिण एशिया में यह संख्या 14 और ओईसीडी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) देशों में यह संख्या 12 है।

7.40 इस क्षेत्र की मदद करने के लिए वर्ष 2013-14 में किए गए अनेक नीतिगत उपायों में एफडीआई नीति में संशोधन किया जाना शामिल है जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम फ्लोर एरिया को पूर्ववर्ती 50000 वर्गमीटर से कम करके 20,000 वर्ग मीटर किया गया और न्यूनतम पूंजी अपेक्षा को 10 मिलियन अमरिकी डॉलर से कम करके 5 मिलियन अमरिकी डॉलर किया गया। वर्ष 2014-15 के बजट में स्थावर सम्पदा निवेश न्याय (आरईआईटी) की स्थापना की भी घोषणा की गई और सेबी ने आरईआईटी विनियमन को मंजूरी दे दी है। बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए आवास में स्वयं रहने पर आवास ऋण पर ब्याज की कटौती सीमा को बजट 2014-15 में 1.5 लाख रुपए की पूर्ववर्ती सीमा से बढ़ाकर 2 लाख रुपए भी कर दिया गया था। कम मंहगे मकानों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए और वर्ष 2022 तक सभी के लिए मकान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सस्ते मकानों को वित्तपोषित करने के लिए बैंकों द्वारा दीर्घावधिक बांड का निर्माण करने से संबंधित मापदण्डों में ढील दी।

आंतरिक व्यापार

7.41 11,47,274 करोड़ रुपए का व्यापार और मरम्मत सेवा क्षेत्र जिसका सकल घरेलू उत्पाद में 11.0 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, में वर्ष 2013-14 में 14.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस श्रेणी में व्यापार एक प्रमुख मद है क्योंकि इस श्रेणी में मरम्मत सेवाओं का हिस्सा केवल 6-7 प्रतिशत है। एटी कर्नी ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स (जीआरडीआई) के अनुसार, भारत वर्ष 2013 के 14वें स्थान से फिसलता हुआ 2014 में 20वें स्थान पर आ गया। वर्ष 2013 में खुदरा क्षेत्र पर उच्च उपभोक्ता मुद्रास्फीति, मुद्रा संबंधी घट-बढ़ और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कठोर नीतियों के कारण असर पड़ा था। लेकिन भारत कई कारणों से दीर्घावधिक खुदरा व्यापार के लिए आकर्षक गंतव्य बना हुआ है। इन कारणों में एक इसकी बड़ी आबादी का होना है, जिसका 58.3 प्रतिशत हिस्सा 30 वर्ष की आयु से कम है और इसका 31.1 प्रतिशत हिस्सा शहरी क्षेत्रों में रहता है जिसके पास बढ़ती खर्च योग्य आमदनी है। पारंपरिक स्टोर से आधुनिक खुदरा व्यवस्था को अपनाने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि आधुनिक खुदरा बाजार कुल बाजार का केवल 8 प्रतिशत है।

7.42 भारत के ई-कॉमर्स बाजार के अगले 5 वर्षों में 50 प्रतिशत से अधिक विकसित हो जाने की संभावना है। भारत में ऑनलाइन खुदरा व्यापार के लिए वस्तु सूची प्रबंधन, सभारिकी योजना और संसाधनों की उपलब्धता बड़ी अड़चने हैं। ई-कॉमर्स के उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा उपाय एक और चिंता का सबब होने के कारण सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण

अधिनियम 1986 में किए जा रहे संशोधन में पर्याप्त उपबंध शामिल करने का प्रस्ताव किया है।

मीडिया और मनोरंजन सेवाएं

7.43 भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग में विभिन्न घटक हैं जिनमें टेलिविजन, प्रिंट, फिल्मों, रेडियो, संगीत, ऐनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स तथा डिजिटल एडवर्टाइजिंग शामिल हैं। फिक्की-केपीएमजी द्वारा दी गई एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग में वर्ष 2013 में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 918 बिलियन रुपए पर जा पहुंचा। इस उद्योग के 14.2 प्रतिशत के सीएजीआर पर बढ़ने की और वर्ष 2018 तक 1786 बिलियन रुपए तक पहुंच जाने की संभावना है। आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र का विकास डिजिटल एडवर्टाइजिंग और गेमिंग द्वारा संचालित किए जाने की संभावना है। 18.4 बिलियन रुपए के अंतर्वाह के चलते इस क्षेत्र ने अप्रैल 2000 से नवम्बर 2014 के दौरान भारत में कुल एफडीआई अंतर्वाहों के 1.6 प्रतिशत का योगदान किया।

7.44 भारत चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद 161 मिलियन टी॰वी॰ परिवारों के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा टी॰वी॰ बाजार है। इस समय भारत में प्रचलनरत लगभग 826 सेटेलाइट टेलिविजन चैनल, 86 टेलिपोर्ट, 243 एफएम रेडियो चैनल और 179 कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन हैं। भारत के प्रसारण वितरण नेटवर्क में 6000 मल्टीसिस्टम आपरेटर (एमएसओ), लगभग 60,000 लोकल केबल आपरेटर (एलसीओ) और 7 डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) आपरेटर हैं। सरकार ने अपने केबल नेटवर्क को चार चरणों में डिजिटल करने की एक महत्वाकांक्षी कवायद शुरू की है जिससे 31 दिसंबर 2016 तक एनालॉग टीवी सेवाएं पूर्णतः समाप्त हो जाएंगी। भारत में प्रसारण क्षेत्र के लिए उदारीकृत एफडीआई व्यवस्था भी बनाई है जहां विषय समग्री में 26 प्रतिशत एफडीआई और डीटीएच, एचआईटीएस, एमएसओ जैसी विभिन्न कैरिज सेवाओं में 74 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है।

7.45 भारत अंतर्राष्ट्रीय स्टूडियो के एक नए प्रिय पात्र के रूप में उभर रहा है और फिल्म क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है। डिजनी, फॉक्स, सोनी और वार्नर ब्रदर्स ने देशी निर्माण घरानों के साथ निर्माण और वितरण समझौते किए हैं। 10 देशों के साथ भारत ने सह निर्माण संधियां की हैं। वर्ष 2014-15 (दिसंबर 2014 तक) के दौरान, सरकार ने 21 विदेशी निर्माण घरानों को भारत में फिल्म शूट करने की अनुमति प्रदान की है।

7.46 संक्षेप में मुश्किल अंतरराष्ट्रीय और घरेलू हालात के बावजूद सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन हाल के वर्षों में काफी अच्छा रहा है। तथापि, विभिन्न क्षेत्रों का प्रदर्शन एक समान नहीं रहा है।